यूपी में बने मोबाइल से 'हेलो' बोल रहा देश

ऐसे बढ़ते गए कदम

आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स

डेटा सेंटर सेक्टर में इन कंपनियों ने किया निवेश (आंकड़े करोड़ रुपये में)

- **9,134.90** एनआईडीपी डिवेलपर
- **5,129** अडाणी इंटरप्राइजेज
- **2,700** सिफी इंडिया
- **2,414** क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
- **1,687** एनटीटी ग्लोबल

आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली में बनेंगे आईटी पार्क

आईटी सिटी, लखनऊ के बाद कुछ और शहरों में आईटी केंद्र स्थापित करने की योजना

2017 से 2022 तक 43,780 लोगों को मिला रोजगार

नोएडा, आईआईटी कानपुर, एसजीपीजीआई में बनाए गए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस

नोएडा में सैमसंग के प्लांट में स्ट्रक्चर प्लान देखते सीएम

जब भारत आजाद हुआ तो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र महज कुछ फोन लाइनों तक सीमित था। '70 के दशक में जब देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने उड़ान भरी तो यूपी में भी काफी विकास हुआ। 1979 में स्थापित अपट्रॉन इंडिया के उत्पादों की धूम देश-विदेश में थी। हालांकि उदारीकरण ने हमें पीछे छोड़ दिया। बाद की कोशिशें रंग लाई और अब दुनिया की बड़ी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। प्रदेश की इस यात्रा पर नजर डाल रहे हैं, आनंद कुमार त्रिपाठी:

पुराना अध्याय समाप्त, सुनहरा दौर हुआ शुरू

1979 में अपट्रॉन इंडिया कंपनी बनी। सरोजनीनगर प्लांट में टीवी और ऐशबाग में कैपेस्टर बनते थे। '90 तक अपट्रॉन के उत्पादों की डिमांड पूरे देश में होती थी।

90 के दशक तक अपट्रॉन के ब्लैक एंड वाइट टीवी पसंदीदा हुआ करते थे।

1990 के बाद बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे महानगरों के विकास में आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। 70 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का चलन बढ़ना शुरू हुआ, तब केवल सरकारी कंपनियां थीं। 1974 में प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) बनाया और इसके चार साल बाद आई अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी। 90 के दशक तक इसके टेलिविजन, टेलिफोन एक्सचेंज, वायरलेस की मांग पूरे देश में थी। भारत सरकार के मंत्रालयों, डीआरडीओ और बीएसएनएल में इसके टेलिफोन एक्सचेंज थे। अपट्रॉन कंप्यूटर भी बनाने लगा था, लेकिन उदारीकरण तमाम देशी कंपनियों पर भारी गुजरा। अपट्रॉन भी अछूती नहीं रही और सुनहरा अध्याय तमाम कोशिशों के बाद भी समाप्त हो गया। सरकारी कंपनियों की जगह निजी कंपनियों ने ले ली।

फिर लौटीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां : साल 2000 के बाद बड़ी संख्या में आईटी कंपनियों ने नोएडा का रुख किया। एचसीएल ने नोएडा में आईटी कंपनी बनाई, लेकिन 2008 में अमेरिका के सबप्राइम संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया पर असर डाला। हालांकि 2012 के बाद जब हालात सामान्य हुए तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने प्रदेश को फिर नया ठिकाना बनाया। शुरुआत नोएडा से हुई। बाद में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यूनिट्स लगीं। साल 2012 के बाद सैमसंग ने नोएडा में अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। एलजी पैनासॉनिक, सीमेंस, हायर जैसी कंपनियां भी नोएडा पहुंचीं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक हब बनकर उभरा। इसी बीच इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेटीएम और टीसीएस जैसी कंपनियों ने दफ्तर खोले। लखनऊ में टीसीएस का दफ्तर तो था ही 2016 में एचसीएल ने आईटी सिटी भी बनाई। टीसीएस ने वाराणसी में कॉल सेंटर भी खोला। मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में एक-एक आईटी पार्क बना है। लखनऊ-कानपुर में एक-एक और आईटी पार्क बन रहा है। गोरखपुर भी इस लिस्ट में जल्द जुड़ जाएगा।

मोबाइल क्रांति के रथ पर यूपी : देश में अगर 100 मोबाइल बनते हैं तो उसमें से 45 यूपी में बनाए जाते हैं। देश में सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट सैमसंग की नोएडा में है। वीवो, ओपो ने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है। मोबाइल एसेसरीज की दुनिया के बड़े नाम सनवोडा, हॉलिटेक, सैमकॉंग, डिक्सन टेक्नॉलजी, एडनर्स, सिमेंस, ऑप्टिमस भी चीन छोड़ नोएडा में हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यूपी में तीन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाए जाने हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी 100 एकड़ में टॉय्ज क्लस्टर बना रही है जबकि बाकी दो लिए जगह तलाशी जा रही। चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान की कई कंपनियां यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में बनने वाले क्लस्टर में प्लांट की इच्छा जता चुकी हैं। डेटा सेंटर के मामले में भी यूपी में पांच कंपनियों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में निवेश किया है। हीरानंदानी समूह पहला डेटा सेंटर बना चुका है। अडाणी ग्रुप के दो डाटा सेंटर बन रहे हैं और एनटीटी व एसटीटी ग्लोबल भी डेटा सेंटर बना रहा। प्रस्ताव सिफी का भी है।

अगले 25 साल का रोडमैप

आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नया एसईजेड कानून जरूरी

2022 के बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल इकॉनमिक जोन (एसईजेड) की बात कही थी, जिसमें राज्यों को भी पार्टनर बनाए जाने का जिक्र था। प्रदेश सरकार को एसईजेड के नए कानून पर बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द लागू हो ताकि आईटी कंपनियों को लाभ मिले। 2006 की एसईजेड पॉलिसी में टैक्स छूट की मियाद पूरी हो चुकी है। यही वजह है कि कोविड के बाद नए निवेश से कंपनियां हिचक रही हैं। इस इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए सरकार को अपने दरवाजे इंडस्ट्री के लिए खोलने होंगे। जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनानी होंगी। सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रोग्राम लागू किए जा सकते हैं।

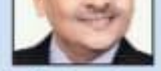

जयंत कृष्णा
सीईओ, फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस ऐंड टेक्नॉलजी

सॉफ्टवेयर के साथ ही हार्डवेयर निर्माण को भी बढ़ावा देना चाहिए। सेमिकंडक्टर यूनिट्स को लेकर केंद्र सरकार योजना लाई है। प्रदेश को भी इसमें पहल करनी चाहिए। सेमिकंडक्टर चिप का निर्माण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड सेमिकंडक्टर असोसिएशन (आईईएसए) ने उम्मीद जताई है कि देश का सेमिकंडक्टर उपकरण बाजार 2026 तक 300 अरब डॉलर का आकार ले सकता है। प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना से घरेलू सेमि-कम्पोनेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। यूपी अगर शुरू में ही सेमिकंडक्टर निर्माण में कदम आगे बढ़ाता है तो इसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। हैदराबाद और बेंगलुरु इनक्यूबेटर (स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले संगठन) पर बहुत काम हुआ है। यूपी को इससे सीखना चाहिए। नए उद्यमियों को ऐसा माहौल देना चाहिए, जिससे उनका स्टार्टअप स्थापित हो सके। सरकार को स्टार्टअप्स के लिए जरूरी रियायतें भी देनी चाहिए। साइंस ग्रैजुएट्स और इंजिनियरों को रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर देना चाहिए।